



AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED

(Formerly known as Devki Leasing and Finance Limited)

CIN: L74110RJ1993PLC085542

Date: 30.05.2025

To,
The General Manager-Listing
Bombay Stock Exchange Limited (BSE)
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai- 400 001.

Script Code - 530765 / Scrip Name - AGARWAL

Subject: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Ma'am,

In accordance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the Newspaper Advertisement Extract of the **Audited Financial Results of the Company for the Fourth Quarter and Financial Year ended March 31, 2025.**, consequent upon the approval of the meeting of the Board of Directors held on **29th May, 2025** and the same was published in Financial Express (English Edition) and Nafa Nuksan (Hindi Edition) on 30.05.2025.

You are requested to kindly take the above on your records.

Thanking You
Yours faithfully

FOR AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED
(Formerly known as Devki Leasing and Finance Limited)

Aditi Parmar
(Company Secretary & Compliance Officer)
M. No.: A37301

Enclosed: as above

For Your Information

Population living
in slums (% of
urban population):



South
Sudan : 94%
Ghad : 82%
Sudan : 74%
Afghanistan : 73%
Niger : 70%
CAR : 69%
Ethiopia : 64%
Ecuador : 58%
Pakistan : 56%
Kenya : 51%
Iraq : 49%
India : 49%
Nigeria : 49%
Nepal : 40%
Source: United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
Compiled by Nafanuksan Research

अमृत वचन



नौकरी के लिए परदेस
ये जाकर तभी बतिया,
जब मात-पिता भी वहां राख
चलने को तैयार हो। कहीं ऐसा
न हो कि वे वहां अनाथों की
तरह बेरहारा हो जाएं।

- श्री एतम

Thoughts of the time

What a sober man has in his
heart, a drunken man has on
his lips

- Danish Proverb

Winner work hard to win,
losers find and excuse to lose!
stop giving excuses!

- Suresh Rathi

राजस्थानी कहावत

घर देख हालणी, मांटी देख मालहणी

घर के हिसाब से चलना, पति के
हिसाब से गरूर करना

- अपने घर की जैसी हैसियत हो, उसी के अनुसार चलना वांछित है।

-सच, विनय दान देना
साधार : रूपायन संस्था, बीकानेर

संसदीय समिति ने दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता में 'अस्पष्टता' पर चिंता जताई

नयी दिल्ली@एजेंसी। संसद की एक समिति ने दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में "अस्पष्टता" पर चिंता जताई है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार मौजूदा चिंताओं को दूर करने के लिए कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

सूत्रों ने कहा कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को रद्द करने का उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय भी भाजपा सांसद भर्तुहर महताब की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति की चर्चा में आया। इस आदेश ने दिवाला तंत्र की दक्षता पर बहस छेड़ दी है। शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को बीपीएसएल के परिसमापन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। पिछले महीने न्यायालय ने इस बारे में फैसला सुनाया था। जेएसडब्ल्यू स्टील ने तर्क दिया था कि परिसमापन उसके, ऋणदाताओं और कर्मचारियों के लिए नुकसान वाला होगा। कॉर्पोरेट मामलों के सचिव और कई बैंकों के प्रतिनिधि समिति के समक्ष पेश हुए। समिति के सदस्यों ने 'दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता' और उभरते मुद्दों के काम की समीक्षा' के एजेंडा पर चर्चा की।

सूत्रों ने कहा कि समिति के कुछ सदस्यों ने समाधान प्रक्रिया में देरी जैसी कमियों के बारे में बताया, और कहा कि जितने सिराहा की अध्यक्षता वाली पिछली समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कानून में कुछ कमियों को उजागर किया था और कुछ बदलावों की सिफारिश की थी। सरकार ने कानून के एक पहले के संशोधन में कुछ सुझावों को शामिल किया था।

फाइनेंशियल ईयर 2024-25

जयपुर बेस्ड शेरा एनर्जी लि. का रेवेन्यू व नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड लेवल पर

जयपुर@का.सं। जयपुर बेस्ड शेरा एनर्जी लिमिटेड प्रमुख रूप से नॉन फेरस मेटल जैसे एल्युमिनियम और कॉपर के वाइडिंग वॉयर एवं रिस्ट्रप् की मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एक्टिव है, जिसने हाल ही में अक्टूबर-मार्च 2025 छमाही व फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के वित्तीय परिणाम जारी किए हैं, जिसमें कंपनी का सॉलिड परफॉर्मेंस दर्ज किया गया है। कंपनी के वित्तीय परिणामों पर नजर डाली जाए तो अक्टूबर-मार्च 2025 छमाही व फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रेवेन्यू व नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है।

कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो अक्टूबर-मार्च 2025 छमाही में कंपनी की रेवेन्यू 37.68 फीसदी बढ़कर 491 करोड़ रुपए के मुकाबले 676 करोड़ रुपए के हो गई। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 62.5 फीसदी बढ़कर 8 करोड़ रुपए के मुकाबले 13 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी की रेवेन्यू 46 फीसदी बढ़कर 875 करोड़ रुपए के मुकाबले 1277 करोड़ रुपए दर्ज की गई, जबकि नेट प्रॉफिट भी 57 फीसदी बढ़कर 14 करोड़ रुपए के मुकाबले 22 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। कुल मिलाकर कंपनी की रेवेन्यू व नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। कंपनी का ऑपरेंटिंग प्रॉफिट भी 51 करोड़ रुपए से बढ़कर 59 करोड़ रुपए हो गया,



अप्रैल-जून क्वार्टर में होगा, जबकि सॉल्विडरि कंपनीज में कॉमर्शियल प्रोडक्शन जुलाई-सितंबर क्वार्टर में शुरू होने की संभावना है। ग्लोबल स्तर पर वाइडिंग वायर इंडस्ट्री में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है, जिसका लाभ कंपनी की ग्रोथ के रूप में मिल रहा है। नया कैपेक्स होने के बाद कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिसके कारण कंपनी की रेवेन्यू व नेट प्रॉफिट में ग्रोथ निरंतर सरटेन करेगी। कंपनी के शेयर शुक्रवार को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर 154 रुपए पर बंद हुए।

हिन्दुस्तान जिंक ने देश का पहला पोटाश और रेयर अर्थ एलिमेंट्स ब्लॉक हासिल किया

उदयपुर@नि.सं। भारत की एकमात्र और दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने दो नए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक हासिल कर भारत के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये दोनो पोटाश और हैलाइट के लिए और दूसरा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए है। कंपनी को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भारत के पहले पोटाश और हैलाइट ब्लॉक और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स ब्लॉक के लिए पर्सदीदा बोलोदाता घोषित किया गया है। यह रणनीतिक जीत हिंदुस्तान जिंक की खनिज की ओर बढ़ती विकास यात्रा में मील का पत्थर है। इस महीने की शुरुआत में कंपनी को बालेपालम टंगस्टन और एसोसिएटेड मिनरल ब्लॉक के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से आशय पत्र भी मिला।

पोटाश उर्वरक उद्योग में प्रमुख खनिज है जिसका उपयोग एनपीके उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। वर्तमान में भारत अन्य देशों से



100 प्रतिशत पोटाश का आयात करता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा कि, भारत के पहले पोटाश ब्लॉक और रेयर अर्थ एलिमेंट्स ब्लॉक को हासिल करना रणनीतिक मिनरल एक्सप्लोरेशन में हमारी क्षमता का प्रमाण है। हम महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और देश के खनिज सुरक्षा लक्ष्यों और तेज आर्थिक विकास का सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं।

नेशनल ● इंटरनेशनल

इंडियन कंपनियां कैपेक्स बढ़ाएं, प्रॉफिट के अनुरूप बढ़ाई जाए सैलेरी भी

नयी दिल्ली@एजेंसी। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने 6.5 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि करने और वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारतीय कंपनियों से अपना कैपेक्स बढ़ाने और लाभप्रदता वृद्धि के अनुरूप कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने को कहा। नागेश्वरन ने 'निवेश के पुण्य चक्र' की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बढ़े हुए निवेश से न केवल क्षमता बढ़ेगी बल्कि अधिक वेतन वाली अधिक नौकरियां पैदा होंगी जिसका नतीजा बढ़ी हुई घरेलू बचत के रूप में निकलेगा। 'निवेश का पुण्य चक्र' एक ऐसी स्थिति है जहां निवेश से उत्पन्न सकारात्मक परिणाम आगे के निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे एक आत्मनिर्भर और लगातार बढ़ती हुई आर्थिक वृद्धि की स्थिति बनती है। उन्होंने कहा, "हम ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं कि लाभप्रदता में

वृद्धि न केवल पूंजी निर्माण में वृद्धि से अधिक हो गई है, बल्कि लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि ने वेतन वृद्धि और भर्तियों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह कुछ ऐसी स्थिति है जिसे हम अगले 25 या 30 वर्षों तक नहीं झेल सकते हैं।"

उन्होंने यहां उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा कि इस तरह की चुनौती का सामना आमतौर पर विकसित देशों को करना पड़ता है, न कि भारत जैसे विकासशील देशों को। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, "उदाहरण के तौर पर, भारत के निजी क्षेत्र की लाभप्रदता मार्च, 2024 तक 7.2 लाख करोड़ रुपये से चार गुना बढ़कर 28.7 लाख करोड़ रुपये हो गई लेकिन दूसरे दशक में पूंजी निर्माण केवल तीन गुना बढ़ा।" उन्होंने कहा, "ऐसे में, लाभप्रदता की वृद्धि दर और निजी क्षेत्र के बीच भरोसा पैदा करना होगा। उन्होंने कहा, "वास्तव में, नियामकीय अतिक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कभी-कभी निजी

क्षेत्र की ओर से उतना विश्वास न होना है। हमारी राय में नियामक कम करने का क्या स्पष्ट है, लेकिन कैसे अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।" उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वास पर आधारित सहयोगी नजरिये की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हम अगले 25 वर्षों में जिस तरह की वृद्धि की उम्मीद करते हैं, उसे तब तक हासिल नहीं कर सकते, जब तक कि न केवल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, बल्कि देश भर की सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच भी सहयोगात्मक दृष्टिकोण न हो।" आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि भारत ने आर्थिक संवर्धन में अनुमानित 6.3-6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है और अच्छे मानसून, सरकारी कैपेक्स में वृद्धि, कर राहत और कम व्याज दर के माहौल के कारण यह लंबे समय तक बरकरार रहेगी।

रिजर्व बैंक के बही-खाते का आकार 33% बढ़कर 76.25 लाख करोड़ रुपये हुआ : वार्षिक रिपोर्ट

मुंबई@एजेंसी। विदेशी मुद्रा लेनदेन में करीब 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रिजर्व बैंक के बही-खाते का आकार बढ़कर 76.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसके दम पर ही केंद्रीय बैंक ने सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये का बड़ा लाभांश दिया है। आरबीआई ने जारी अपनी 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि देश वित्त वर्ष 2025-26 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसमें कहा गया कि दीर्घकालीन भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के बीच, मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचे और सक्रिय नीतिगत उपायों के समर्थन से 2024-25 में अर्थव्यवस्था ने जुझारू क्षमता दिखाई।

रिपोर्ट में कहा गया, " वित्तीय क्षेत्र की मजबूती (जो बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकों में परिलक्षित होती है) ने आर्थिक गतिविधियों को और अधिक समर्थन दिया। कई वैश्विक

चुनौतियों के बीच, भारतीय वित्तीय बाजारों ने जुझारू एवं व्यवस्थित गतिविधियों का प्रदर्शन किया।" इसने वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार विखंडन, आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं को वृद्धि के दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए सकारात्मक पहलू के रूप में चिह्नित किया। रिजर्व बैंक ने कहा कि हालांकि, आपूर्ति-श्रृंखला पर दबाव में कमी, वैश्विक ज़िंस कीमतों में नरमी और सामान्य से बेहतर दक्षिण-पश्चिम मानसून से कृषि उत्पादन में वृद्धि जैसे कारक मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए अच्छे संकेत हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि शुल्क नीतियों में बदलाव के चलते वित्तीय बाजारों में कहीं-कहीं अस्थिरता का प्रभाव दिख सकता है और निर्यात को "अंतर्मुखी नीतियों एवं शुल्क युद्ध" के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

बीफ न्यूज

लघु उद्योग भारती ने पाली व सिरोही जिले की इकाइयों का किया गठन

जोधपुर@नि.सं। लघु उद्योग भारती के जोधपुर प्रांत अध्यक्ष महावीर चौपड़ा, प्रांत महासचिव विनय बंब व प्रांत संयुक्त



महासचिव सुरेश कुमार विश्वांनी ने पाली व सिरोही जिले के प्रवास के दौरान जिलों में वर्ष 2025-27 के लिए नवीन कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों, इकाई विस्तार, सदस्यता अभियान को गति देने, आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक विभिन्न समस्याओं और सुझावों पर विचार-विमर्श कर उनका निराकरण करवाने का निर्णय लिया गया। चौपड़ा ने केंद्र व राज्य स्तर पर उद्योगों के हितार्थ किये जा रहे कार्यों के विषय में विस्तारपूर्वक बताया। सिरोही जिले की रेवदर इकाई की नवीन कार्यकारिणी 2025-2027 की घोषणा की गयी, जिसमें अध्यक्ष पद का दायित्व मगनलाल, उपाध्यक्ष कीर्तिमान एवं मानाराम, सचिव विक्रम भाई, सहसचिव भोलाराम एवं कोषाध्यक्ष गुलाब भाई माली को दिया गया। सिरोही इकाई की वर्ष 2025-27 के लिये नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें इकाई अध्यक्ष का दायित्व विनोद पंवार, सचिव सुरेश चौधरी, उपाध्यक्ष विकास कंसारा एवं कोषाध्यक्ष अरविन्द डागा को दिया गया। बैठक के उपरान्त प्राप्त पदाधिकारियों द्वारा कांसा इंडस्ट्रीज का भी अवलोकन किया गया। इसी प्रकार पाली शहर में स्थित विभिन्न इकाइयों की वर्ष 2025-27 के लिये नवीन कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए मण्डिया इकाई अध्यक्ष का दायित्व पुनः सम्पत्त संखलेचा, सचिव वरुण सिंघेल, पुनायता औद्योगिक क्षेत्र इकाई अध्यक्ष निलेश सेमलानी, सचिव राजेश चौधरी, पाली सेन्ट्रल इकाई अध्यक्ष महेंद्र तातेड़ एवं सचिव महावीर चौपड़ा को दिया।

खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने गेहूं की स्टॉक सीमा का विरोध जताया

जयपुर@का.सं। केंद्र सरकार ने 27 मई को एक आदेश जारी करके व्यापारी व थोक विक्रेता के लिये स्टॉक सीमा 3 हजार मीट्रिक टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिये 10 मीट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर के लिये प्रत्येक आउटलेट के लिये 10 मीट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर की दुकानों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिये। प्रोसेसर्स यानि आटा मिल के लिये मासिक स्थापित क्षमा के 70 प्रतिशत मात्रा को 2025-26 के शेष महीनों से गुणा के बराबर स्टॉक सीमा रहेगी। स्टॉक सीमायें उपर्युक्त के अनुसार संबंधित विधिक इकाईयां, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेगी और यदि उनके पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है तो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा में स्टॉक लाएंगे। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने इस आदेश का विरोध दर्ज करते हुए बताया कि देश में गेहूं की पैदावार गत वर्ष 1133 लाख टन थी और इस वर्ष बढ़कर व्यापारिक अनुमान से 1154 लाख टन के करीब गेहूं का उत्पादन हुआ है। जबकि गेहूं का गत वर्ष का केरिऑवर स्टॉक पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक है। बाजारों में गेहूं के भाव अभी भी 25 से 28 रुपये किलो थोक में उपलब्ध है। मण्डियों में गेहूं की आवक बनी हुई है। एफसी.आई. द्वारा खरीद किया गया गेहूं मण्डियों में पड़ा हुआ है। एफसी.आई. इस गेहूं को उठा नहीं पा रही है। ऐसे में स्टॉक सीमायें लगाना अनुचित है।

मार्च तक 1,016 करोड़ रुपये का ई-रुपया चलन में, सीमा पार भुगतान पर भी विचार : आरबीआई रिपोर्ट

मुंबई@एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि देश में डिजिटल मुद्रा का चलन बढ़ रहा है। मार्च 2025 के अंत तक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) या ई-रुपये का मूल्य बढ़कर 1,016 करोड़ रुपये हो गया जो इससे एक साल पहले 234 करोड़ रुपये था। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि सीबीडीसी के जरिये सीमापार भुगतान को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हालांकि उसने इस बारे में कोई समयसीमा नहीं बतायी। सीबीडीसी को पहली बार नवंबर 2022 में थोक लेन-देन के लिए प्रायोगिक आधार पर पेश किया गया था। उसके बाद खुदरा लेनदेन के लिए इसे पेश किया गया। सीमापार भुगतान को सरल बनाना सीबीडीसी के घोषित लक्ष्यों में से एक है। सरकारी बिटकॉइन जैसी गैर-सरकारी डिजिटल मुद्राओं से मुद्रा प्रणाली के समक्ष उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए डिजिटल मुद्रा को पेश किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा, "रिजर्व बैंक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों आधारों पर सीमा पार भुगतान के लिए परीक्षण आधार पर सीबीडीसी शुरू करने की संभावना तलाश रहा है। इसका मकसद भुगतान में लगने वाले समय, दक्षता और पारदर्शिता से जुड़ी चुनौतियों से पार पाना है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनिंदा देशों के साथ पायलट आधार पर द्विपक्षीय सीमापार सीबीडीसी की संभावना टटोली जा रही है। इस संदर्भ में रूपरेखा, तकनीकी पहलुओं और उपयोग के मामलों को अंतिम रूप देने में प्रगति हुई है। बहुपक्षीय सीबीडीसी पहल में रिजर्व बैंक की विशेष रूप से 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) इनोवेशन हब' के तहत भागीदारी पर भी विचार किया जा रहा है। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य नये उपयोग के मामलों और सुविधाओं को पेश करके ई-रुपया-खुदरा और ई-रुपया-थोक में चल रहे पायलट परियोजनाओं के दायरे का और विस्तार करना है।

AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED (Formerly known as Devki Leasing and Finance Limited) CIN: L74110RJ1999PLC088542					
Registered Office: S-9-A, 2nd Floor, Sagar Ratna, Gopalpura Bypass Road, Shri Gopal Nagar, Jaipur - 302019 Corporate Office: Third Floor, F-2264, RHCO Industrial Area, Ramchandrapura, Jaipur - 302022 Email Id: afg@agajar@gmail.com Website: www.agarwalfortune.com Contact: 91-7230643249					
Extract of the Audited Financial Results for the Fourth Quarter and Year Ended March 31, 2025					
PARTICULARS	Quarter ended			Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
	31.03.2025 (Audited)	31.12.2024 (Un-Audited)	31.03.2024 (Audited)		
Total Income from operations (net)	232.89	43.68	183.47	448.45	754.04
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	9.69	3.84	1.11	19.47	9.72
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	9.69	3.84	1.11	19.47	9.72
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.69	3.84	1.11	19.47	9.72
Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	9.69	3.84	1.11	19.47	9.72
Equity Share Capital	343.54	343.54	343.54	343.54	343.54
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-					
Basic	0.28	0.11	0.03	0.57	0.28
Diluted	0.28	0.11	0.03	0.57	0.28
Note: 1. The above results for the quarter and year ended March 31, 2025 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 29.05.2025. 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results is available on the website of Stock Exchanges (www.bseindia.com) and also on the Company's website. For AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED (MAHESH KUMAR AGARWAL), Managing Director (DIN:02806108)					
Date: 29.05.2025 Place: Jaipur					